



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार 02 मार्च, 2017 / 11 फाल्गुन, 1938

हिमाचल प्रदेश सरकार

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22nd February, 2017

No-TPT-B(1)-15/2000-Loose-I.—In partial modification of this department Notification No. TPT-B(1)-15/2000-Loose dated 24th August, 2003, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order to fill up 12 posts of Traffic Inspectors Class-III (Non-Gazetted) of two units of Flying

Squad under Transport Department by promotion amongst the Departmental officials and direct recruitment/secondment basis from HRTC in the ratio of 50:50 respectively in the following manner:—

- 50% from direct recruitment/on secondment basis from HRTC.
- 30% from amongst the Drivers of Transport Department.
- 10% from Clerks of the Transport Department.
- 10% from Steno Typist of the Transport Department.

By order,
SANJAY GUPTA,
Principal Secretary(Transport).

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd February, 2017

No. TPT-F (1)-3/2015-I.—In partial modification of this department Notification No. Tpt. F(1)-4/1996-V dated 05.03.2014 and Notification No. Tpt-F(1)-3/2015 dated 20-02-2016, the Governor, Himachal Pradesh in pursuance of the powers conferred under clause (iii) of proviso to sub rule (1) of rule 108 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989 and all other powers enabling him in this behalf, is pleased to allow/specify the following dignitaries to use Red/Blue Light to the front top of their official vehicles. This notification will be effective from the date of publication in Himachal Pradesh Rajpatra:—

1. Red Light with flasher:

- (i) Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh.
- (ii) President/Chairman, H.P. State Consumer Dispute Redressal Commission.

2. Blue Light with flasher:

- (i) Chief Commissioner, Income Tax, H.P.
- (ii) Principal Commissioner, Income Tax, H.P.

By order,
SANJAY GUPTA,
Principal Secretary (Transport).

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 21 फरवरी, 2017

संख्या: टी0पी0टी0-एफ (7)-1/2017.—राज्य के नागरिकों को सुव्यवस्थित, सुरक्षित यातायात एवं सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था उपलब्ध करवाने व इनका वातावरण पर प्रभाव कम करने हेतु हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित निधि का गठन करते हैं; अर्थात्:—

1. **नाम.**—यह निधि हिमाचल प्रदेश परिवहन आधारभूत विकास निधि 2017 कहलएगी।
2. **प्रभावशीलता.**—यह निधि 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावशील होगी।
3. **परिभाषाएं:—**
 1. “निधि” से तात्पर्य हिमाचल प्रदेश परिवहन आधारभूत विकास निधि-2017 है।
 2. “राज्य सरकार” से आशय हिमाचल प्रदेश सरकार से है।
 3. “सड़क सुरक्षा निधि” से आशय हिमाचल प्रदेश सड़क सुरक्षा कार्य निधि-2006 है।
 4. “नोडल विभाग” से तात्पर्य परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश से है।
 5. “वित्तीय वर्ष” का आशय 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि से है।
 6. “वित्त विभाग” से आशय हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग से है।
 7. बजट नियायक समिति (बी.एफ.सी.) से आशय वित्त विभाग द्वारा गठित समिति जो बजट प्रस्तावों का परीक्षण करके अनुमोदित करती है, से है।
 8. “व्यक्तिगत निक्षेप खाते” से आशय राजकीय संस्था के राज्य के कोष कार्यालयों में खोले गए ऐसे खाते से है जिसमें सामान्यतः राज्य सरकार द्वारा राशि हस्तान्तरित की जाती है।
4. **निधि के गठन के उद्देश्य:—**
 1. राज्य के नागरिकों को सुव्यवस्थित, सुरक्षित यातायात एवं सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था उपलब्ध करवाना,
 2. प्रदूषण रहित यातायात सुनिश्चित करने हेतु प्रदूषण रहित इंधन, तथा L.P.G. & C.N.G. इत्यादि वाहनों की व्यवस्था हेतु राजकीय संस्थाओं को अनुदान, ऋण, अंश-पूंजी उपलब्ध करना,
 3. यातायात के साधनों से उत्पन्न प्रदूषण के प्रभाव को न्यून करने के उद्देश्य से सड़कों के दोनों ओर व विभाजक में तथा शहर में उपलब्ध राजकीय/सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण करना एवं उनका संरक्षण करना, तथा

4. सड़क सुरक्षा निधि के माध्यम से सड़क से सड़क सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी एवं गतिशील बनाने के लिए किए जा रहे कार्यों की आंशिक लागत वहन करना।

5. निधि के आय के स्रोत:—

1. हिमाचल मोटर यान कराधान अधिनियम 1972 के तहत देय एक वारीय अथवा एक मुश्त कर पर 10 प्रतिशत तथा अन्य करों पर 5 प्रतिशत अधिभार से प्राप्त राशि;
2. पुराने तथा नवीन वाहनों पर अधिरोपित ग्रीन टैक्स से प्राप्त राशि का 5% के हिसाब से,
3. राज्य सरकार की संचित निधि से अंशदान के रूप में उपलब्ध कराई जाने वाली राशि,
4. निधि के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु केन्द्र सरकार तथा अन्य सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों से प्राप्त राशि,
5. औद्योगिक संस्थाओं से, सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत प्राप्त राशि, तथा
6. अन्य स्रोत जिन्हें समय-समय पर विशिष्ट रूप से निर्धारित किया जाए।

6. नोडल विभाग:—

1. निधि के प्रबन्ध एवं संचालन के लिए परिवहन विभाग उत्तरदायी होगा। परिवहन सचिव, इस उद्देश्य के लिए नोडल अधिकारी होंगे इस निधि के लिए प्रशासनिक विभाग परिवहन विभाग होगा।
2. इस निधि की 50 प्रतिशत राशि का उपयोग परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा निधि 2006 के अनुसार किया जाएगा। 25 प्रतिशत राशि का उपयोग हिमाचल प्रदेश शहरी परिवहन एवं बस अड्डा प्रबन्धन एवं विकास प्राधिकरण (HPCT & BSM & DA) के माध्यम से किया जायेगा यह राशि cluster के आकार के अनुसार वितरित की जाएगी व शेष 25 प्रतिशत राशि का उपयोग संचालन समिति द्वारा निर्धारित वरियता के आधार पर किया जाएगा।

7. कार्यकारी अभिकरण (Implementing Agencies) :—

1. निदेशक परिवहन हिमाचल प्रदेश
2. हिमाचल प्रदेश शहरी परिवहन एवं बस अड्डा प्रबन्धन एवं विकास प्राधिकरण (HPCT & BSM & DA).
3. उक्त के अतिरिक्त किसी योजना विशेष के क्रियान्वयन हेतु आवश्यकता होने पर संचालन समिति की स्वीकृति से किसी अन्य राजकीय विभाग या राजकीय उपक्रम/संस्था को भी कार्यकारी अधिकरण बनाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में योजना विशेष के सफल क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु सम्बन्धित विभाग/संस्था उत्तरदायी होंगे।

8. संचालन समिति :—

- (1) निधि की धन राशि के उपयोग हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संचालन समिति होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे—

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. सचिव, परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश | सदस्य |
| 2. वित्त सचिव हिमाचल प्रदेश | सदस्य |

3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (HPCT & BSM & DA)	सदस्य
4. निदेशक शहरी विकास हिमाचल प्रदेश	सदस्य
5. निदेशक परिवहन हिमाचल प्रदेश	सदस्य
6. अतिरिक्त निदेशक, परिवहन हि0प्र0	सदस्य सचिव

(2) समिति के कार्य :-

1. निधि के उद्देश्यों की प्राप्ति के क्रम में विभिन्न विभागों एवं कार्यकारी अभिकरणों द्वारा तैयार किए गए प्रोजेक्ट, कार्यक्रम एवं योजनाओं को निधि से राशि उपलब्ध कराने के लिए अनुमोदित करना।
2. विभागों तथा कार्यकारी अभिकरणों द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की नियमित अन्तराल पर समीक्षा करना।
3. निधि के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु नई योजनाएं एवं प्रोजेक्ट तैयार करवाना।
4. योजनाओं की क्रियान्विति के लिए आवश्यक होने पर नई संस्थागत व्यवस्था निधारित करना।

9. निधि का उपयोग:—निधि की धनराशि में से 50 प्रतिशत राशि का उपयोग परिवहन विभाग के माध्यम से तथा 25 प्रतिशत राशि का उपयोग (HPCTBSM & DA) के माध्यम से किया जाएगा व शेष 25 प्रतिशत राशि का उपयोग संचालन समिति द्वारा निर्धारित वरियता के आधार पर निम्न अनुसार होगा :-

अ निधि की धन राशि से निम्नलिखित मदों पर व्यय अनुमत होगा :-

निम्नांकित कार्य/परियोजनाओं के लिए, जो राजकीय विभागों या कार्यकारी अभिकरणों या सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी (PPP) या संयुक्त उपक्रम (JV) या विशेष प्रयोजन माध्यम साधन, संस्था (SPV) के माध्यम से, क्रियान्वित की जा रही है, निधि को अंशदान उपलब्ध कराया जा सकेगा :-

1. प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से प्रदूषण रहित इंधन, तथा C.N.G. & L.P.G. इत्यादि वाहनों की व्यवस्था हेतु सहायता उपलब्ध करवाना।
2. शहरी यातायात में, न्यूनतम कार्बन उत्सर्जित करने वाले वाहनों, आवाज रहित टायरों (Silent Tyres) तथा ध्वनि अवशोषण रोड़ धरातल (Road surface) को प्रोत्साहित करना ताकि पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रित हो सके।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कार्य जो निधि के उद्देश्यों की प्राप्ति के अनुक्रम में हों, संचालन समिति की स्वीकृति से करवाए जा सकेंगे।

व. निधि की धन राशि से, निम्नलिखित मदों पर व्यय पूर्णतः वर्जित होगा :-

1. भूमि एवं भवनों के अधिग्रहण हेतु मुआवजे का भुगतान।
2. सामान्य मरम्मत एवं संधारण पर व्यय।
3. वेतन भत्तों पर व्यय।

4. चुनाव, वी.आई.पी. मूवमेन्ट अथवा किसी अभियान में यातायात व्यवस्था पर व्यय।
5. देश/विदेश में प्रशिक्षण, सेमीनार, वर्कशॉप, बैठकों एवं नवाचार के अध्ययन हेतु विभागीय अधिकारियों के भाग लेने हेतु व्यय।
6. नोडल विभाग से सम्बन्धित राजकीय विभागों में संस्थापर संबंधी नियमित व्यय ताकि अनावर्तक मद (Non-Recurring) वाहन क्रय, वाहन किराया, टेलीफोन, मोबाइल, कम्प्यूटर क्रय, कार्यालय सामग्री क्रय इत्यादि।

10. निधि के उपयोग की प्रक्रिया :—

1. राजकीय विभाग/कार्यकारी अभिकरण (Programme Implementing Agencies) द्वारा कार्य/प्रोजेक्ट के तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे।
2. कार्यकारी अभिकरण, अपने प्रस्ताव सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के अनुमोदन उपरान्त संचालन समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेंगे। परिवहन विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि वर्ष के दौरान निधि का उपयोग निर्धारित अनुपात अर्थात् निधि की 50 प्रतिशत राशि का उपयोग परिवहन विभाग द्वारा, 25 प्रतिशत राशि का उपयोग हिमाचल प्रदेश शहरी एवं बस अड्डा प्रबन्धन एवं विकास प्राधिकरण (HPCT & BSM & DA) के माध्यम से व शेष 25 प्रतिशत राशि का उपयोग संचालन समिति द्वारा निर्धारित वरियता के आधार पर ही हो।
3. संचालन समिति राजकीय विभागों एवं कार्यकारी अभिकरणों से प्राप्त प्रस्तावों पर महत्व एवं आवश्यकता के मद्देनजर विचार कर उचित निर्णय लेगी। जिन कार्य/योजनाओं के प्रस्तावों हेतु वित्त विभाग का अनुमोदन आवश्यक है, प्राप्त किया जाएगा।
4. नोडल विभाग (परिवहन विभाग), निधि में राजस्व प्राप्ति के आंकलन के आधार पर वार्षिक कार्य-योजना तैयार कर बी.एफ.सी. (Budget Finalizing Committee) के समक्ष उपयुक्त बजट प्रावधान हेतु प्रस्तुत करेंगे।
5. बी.एफ.सी. से प्रस्तावों के अनुमोदन उपरान्त बजट अनुभाग द्वारा, सम्बन्धित बजट शीर्षों में राशि का प्रावधान किया जाएगा। वर्ष के दौरान योजना के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर वित्त विभाग के माध्यम से आवश्यक प्रावधान स्वीकृत कराए जाएंगे।
6. अगर कार्य राजकीय विभागों द्वारा सम्पादित किए जाने हैं तो उनके द्वारा इस बजट प्रावधान का उपयोग कोषालय व्यवस्था के माध्यम से किया जाएगा।
7. अगर कार्य/योजना का क्रियान्वयन कार्यकारी अभिकरण द्वारा किया जाना है तो सम्बन्धित राजकीय विभाग उस कार्य/योजना विशेष की वित्त (व्यय) विभाग की सहमति से प्रशासनिक स्वीकृति जारी करेंगे तथा वित्तीय स्वीकृति के आधार पर वित्त (बजट) विभाग द्वारा कार्यकारी अभिकरण के व्यक्तिगत निक्षेप खाते (P.D. A/C) में हस्तान्तरित की जाएगी।
8. कार्यकारी अभिकरण, कार्य/योजनाओं की वित्तीय तथा भौतिक प्रगति से निधि के नोडल विभाग को, मासिक आधार पर, अवगत कराएंगे।
9. निधि की संचालन समिति, कार्य/योजनाओं/प्रोजेक्ट की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की नियमित अन्तराल पर समीक्षा करेगी एवं सुनिश्चित करेगी कि कार्य/योजना, स्वीकृति के अनुसार एवं निर्धारित समय में पूर्ण हों।

10. कार्य पूर्ण होने के तीन माह में, कार्यकारी अभिकरण/राजकीय विभाग द्वारा, कार्य-पूर्णता रिपोर्ट तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र नोडल विभाग (परिवहन विभाग) को प्रस्तुत किए जाएंगे।

11. निधि की राशि से बनी परिसम्पत्तियों पर, कार्यकारी अभिकरण या राजकीय विभाग का स्वामित्व होगा तथा इन परिसम्पत्तियों का नियमित संधारण, विभाग/संस्थाओं के नियमित बजट से किया जाएगा।

12. कार्य/योजनाएं/प्रोजेक्ट स्वीकृत करने की शक्तियाँ (Schedule of Powers):—नियमों में उल्लेखित उद्देश्यों हेतु संचालन समिति द्वारा निम्नानुसार स्वीकृतियां दी जा सकेंगी :—

1. राजस्व प्रकृति के व्यय हेतु।
2. रुपये 5.00 करोड़ से अधिक लागत के पूंजीगत कार्य संचालन समिति की अनुशंसा पर, वित्त विभाग की सहमति उपरान्त स्वीकृत किए जाएंगे। उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक कार्य/योजनाएं/परियोजनाएं जिनके लिए इन नियमों के अन्तर्गत निधि से राशि उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है उनसे संबंधित समस्त प्रस्ताव वित्त विभाग की सहमति उपरान्त ही स्वीकृत किए जा सकेंगे।

13. निधि का लेखांकन :—संचालन समिति द्वारा अनुमोदित व्यय हेतु निधि में उपलब्ध धन राशि को, परिवहन विभाग के बजट मदों के जरिये व्यय किया जायेगा। उक्तानुसार परिवहन विभाग के बजट शीर्षों में बजटीय प्रावधान हेतु अपेक्षित समन्वय करने का दायित्व नोडल विभाग (परिवहन विभाग) का होगा। बजट प्रावधान के प्रस्ताव परिवहन विभाग द्वारा ही प्रस्तुत किए जाएंगे। निधि की प्राप्तियों एवं निधि से व्यय से सम्बन्धित विवरण-पत्र तथा अपेक्षित रजिस्टर संधारण करने का उत्तरदायित्व नोडल विभाग का होगा।

14. अंकेक्षण:—निधि की प्राप्तियों एवं व्यय के नोडल विभाग में संधारित लेखों का अंकेक्षण निदेशक, स्थानीय निरीक्षण विभाग द्वारा किया जायेगा। अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति, निधि की संचालन समिति तथा वित्त (व्यय) विभाग को भी प्रस्तुत की जाएगी।

आदेश द्वारा,
संजय गुप्ता,
प्रधान सचिव (परिवहन)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. TPT-F(7)-1/2017 dated 21.02.2017 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 21st February, 2017

No. TPT-F (7)-1/2017.—In order to provide organized and safe traffic and public transport and to mitigate its effects on environment the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by article 162 of the Constitution of India, is pleased to create the following fund namely:—

1. Short title.—The Fund may be called the Himachal Pradesh Transport Infrastructure Fund.

-
- 2. Commencement.**—The fund will become operational from 1st April, 2017.
- 3. Definitions.**—Unless the subject or context otherwise requires:
1. **‘Fund’** means Himachal Pradesh Transport Infrastructure Development Fund.
 2. **“State Government”** means Government of Himachal Pradesh.
 3. **‘Road Safety Fund’** means Himachal Pradesh Road Safety Fund-2006.
 4. **‘Nodal Department’** means Transport Department, Himachal Pradesh.
 5. **‘Financial Year’** means duration starting from 1st April and ending at 31st March.
 6. **‘Finance Department’** means Finance Department, Government of Himachal Pradesh.
 7. **‘Budget Finalising Committee’** means committee constituted by Finance Department that approves Budget proposals after examining them.
 8. **‘Personal Deposit Account’** means those accounts of Government Institutes opened in Treasury Office in which State Government transfer funds.
- 4. Objectives.**—The objectives of Himachal Pradesh Transport Infrastructure Development Fund are:
- (a) To provide organized and safe traffic and public Transport.
 - (b) To provide incentives to encourage the use of alternate fuels such L.P.G & C.N.G etc., for pollution free environment.
 - (c) To encourage plantation and its maintenance by the road side, to mitigate the effects the pollution.
 - (d) To partly fund Road Safety activities to make the roads of the State safer for the users.
- 5. Sources.**—The Himachal Pradesh Transport Infrastructure Development Fund is proposed to be generated from the following sources:
- (a) By imposing 10% cess on one time tax and 5% cess on other taxes levied under Himachal Motor Vehicle Taxation Act, 1972.
 - (b) Amount received at the rate of 5% of green tax charged from old and new vehicles.
 - (c) Amount received as Grant from consolidated fund of the State Government.
 - (d) Amount contributed by the Central Government, State Government and other Non Governmental Organisation to fulfill the objectives of the Fund.
 - (e) Amount received from Industrial Institutions under Corporate Social Responsibility.
 - (f) Other sources which are decided for the purpose from time to time.

6. Nodal Department.—The Transport Department will be responsible for management and running of the Fund. For this purpose Secretary (Transport) to the Government of Himachal Pradesh will be Nodal Officer and Transport Department will be Administrative Department.

7. Implementing Agencies.—The following will be the implementing agencies for the effective implementation of the fund:

- (a) Director, Transport, Himachal Pradesh
- (b) Chief Executive Officer, Himachal Pradesh City Transport and Bus Stand Management and Development Authority.
- (c) Apart from the above, for implementation of any special scheme, after approval from Managing Committee, any Government Department or Government Undertaking/Organization could be designated as implementing agency. In such case the concerned department/organization will be responsible for the successful supervision and implementation of the said scheme.

8. Managing Committee.—The Himachal Pradesh Transport Infrastructure Development Fund will be managed by a committee constituting of the following:

- | | |
|--|--------------------------|
| (a) Chief Secretary to the Govt. of H.P. | <i>Chairman</i> |
| (b) Secretary (Transport) to the Govt. of H.P. | <i>Member</i> |
| (c) Secretary (Finance) to the Govt. of H.P. | <i>Member</i> |
| (d) Chief Executive Officer, HPCTBSMDA | <i>Member</i> |
| (e) Director, Urban Transport, H.P. | <i>Member</i> |
| (f) Director, Transport, H.P. | <i>Member</i> |
| (g) Additional Director, Transport, H.P. | <i>Member Secretary.</i> |

(B) Functions of Managing Committee:

- (i) To approve/sanction amount from the Fund to the projects, programmes, schemes proposed by various departments and programme implementing agencies that fulfill the objectives of the Fund.
- (ii) To review, on regular intervals, the financial and physical progress of the schemes being implemented by various departments and agencies.
- (iii) To formulate new schemes and projects to achieve the objectives of the Fund.
- (iv) To create new Institutional System, if required, for successful implementation of Schemes.

(C) Schedule of Powers.—To fulfill the objectives of the Fund the Managing Committee can approve the following:

- (i) For expenditure of revenue nature.
- (ii) The works having capital expenditure of more than ₹ 5 Crore, will be undertaken after the recommendation of Managing Committee and approval of Finance Department.

- (iii) All the proposals of the works/Schemes/projects undertaken for fulfillment of objectives of the Fund and for whom amount could not be allocated from the Fund, will be undertaken after the approval of Finance Department.

9. Utilisation of Fund.—The 50% of the amount received under Himachal Pradesh Transport Infrastructure Development Fund is to be utilized through the Transport Department and 25% through the Himachal Pradesh City Transport and Bus Stand Management and Development Authority and remaining 25% of the amount will be utilized according to the priorities fixed by the Managing Committee as per the following:

- A. The spending from the Fund will be permitted on the following works/schemes that are being implemented through Government Departments or Programme Implementing Agencies or through Public Private Partnership or Joint Venture or Special Purpose Venture:
- (i) Schemes to encourage pollution free fuel and C.N.G and L.P.G etc Vehicles for controlling pollution.
 - (ii) To encourage, minimum Carbon emission of vehicles, silent tyres and sound absorbing road surface in Urban Transport, for controlling various forms of environmental pollution.
 - (iii) Apart from these, any other work which is in line with the objectives of the Fund, and approved by the managing committee.
- B. The expenditure from the Fund, on the following heads, will be totally prohibited:
- (i) Compensation for acquired land and buildings.
 - (ii) Expenditure on general repair and maintenance.
 - (iii) Expenditure on salary and allowances.
 - (iv) Expenditure on traffic management for election, VIP movement or any other such campaign.
 - (v) Expenditure on National/International Training, Seminars, Workshops, Meetings and for attendance of departmental officers to study new innovations.
 - (vi) Non recurring Expenditure on rent of vehicles, purchase of vehicles, telephone, mobile, computers, office stationery etc., of Nodal Department and related State Departments.

10. Procedure for Utilisation of fund:—

- (a) Government Departments/Programme Implementing Agencies will prepare Technical and Financial proposals of the Works/Projects.
- (b) Programme Implementing Agencies will place its proposals, after approval from concerned Administrative Department, before the Managing Committee for approval. The Transport Department will ensure that Fund is being utilized in approved proportions that is the 50% of the Fund is being utilized by the Transport Department and 25% by the Himachal Pradesh City Transport and Bus Stand Management and Development Authority and remaining 25% as per the priorities fixed by the Managing Committee.

- (c) The Managing Committee will consider the proposals of Government Departments and Programme Implementing Agencies keeping in view the importance and need of the proposal and will take appropriate decision. The approval of Finance Department will be taken for works/schemes wherever required.
- (d) Nodal Department will prepare Annual Action Plan after assessing the revenue received in the Fund and will place it before the Budget Finalising Committee for making appropriate budget provisions.
- (e) After taking approval of Budget Finalising Committee, the Budget Section will make provision of Funds in the concerned Budget Heads. If during the year, additional sum is required for fulfilling the objectives of the Fund, the necessary provisions will be approved through Finance Department.
- (f) If the work is to be undertaken through Government Department then they will use the Budget provision through Government Treasury.
- (g) If the work/project is to be implemented through Programme Implementing Agencies then the concerned Government Department will issue Administrative Approval after getting approval from Finance (Expenditure) Department and as per the approval of Finance Department, the Finance (Budget) Department will transfer the amount to Personal Deposit Account of the Programme Implementing Agencies.
- (h) Programme Implementing Agencies will inform Nodal Department of the financial and physical progress of the works/schemes on the monthly basis.
- (i) The Managing Committee of the Fund will review the financial and physical progress of the works/schemes/ projects on regular intervals and will ensure that the works/schemes are being implemented as approved and within the approved time frame.
- (j) Within three months of the completion of the work, Programme Implementing Agencies/Government Department will submit work completion report and Utility certificate to the Nodal Department.
- (k) The assets created from the fund will be owned by the Programme Implementing Agencies/Government Department and the regular maintenance of these assets will be undertaken by the Department/Agencies from the regular budget.

11. Accounting of the Fund.—For expenditure approved by the Managing Committee, the amount will be released through the budget heads of Transport Department. It will be the responsibility of Nodal Department to coordinate between Budget Heads of Transport Department and Budgetary provisions. The proposal for making Budget provisions, will be made by Transport Department. The Statement of receipts of Funds and expenditure from fund and expected maintenance of Register is also the responsibility of the Nodal Department.

12. Audit.—The receipt and expenditure accounts as maintained by Nodal Department will be audited by Director, Local Audit Department. The copy of Audit Report will be placed before Managing Committee and Finance (Expenditure) Department.

By order,
SANJAY GUPTA,
Principal Secretary (Transport).

MEDICAL EDUCATION DEPARTMENT**NOTIFICATION***Shimla-2, the 27th February, 2017*

No: HFW-B(B)1-4/2015.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order creation of “**Gastroenterology Surgery Cell**” under the General Surgery department of IGM, Shimla, alongwith following post of faculty member in the “Gastroenterology Surgery Cell”, in the public interest, with immediate effect.

Sl. No.	Category of post	Pay scale	Total number of post
1.	Assistant Professor	Rs. 37400+67000 + GP of Rs. 8900	(1) One

2. This issue with the prior concurrence of the Finance Department obtained *vide* their UO No: 53840881, dated 10-01-2017.

By order,

Sd/-

*Principal Secretary (Health).***बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग**

अधिसूचना

शिमला-2, 27 फरवरी, 2017

संख्या: एम0पी0पी0-एफ(10)-17/2012-I.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, इस विभाग की अधिसूचना संख्या: एम0पी0पी0-एफ(10)-17/2012 तारीख 10-09-2014 और 29-08-2015 के क्रम और आंशिक उपान्तरण में, हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 2009 की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विद्युत शुल्क निर्धारित करते हैं;

- (क) 01-08-2015 को और इसके पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ करने वाली नई औद्योगिक इकाईयां; और
- (ख) विद्यमान औद्योगिक इकाईयां जिन्होंने 31-03-2016 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है और जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में समय-समय पर यथा संशोधित औद्योगिक इकाईयों को अनुदान रियायतें और प्रसुविधाओं से सम्बन्धित नियम, 2004 के अधीन यथा परिभाषित ऐसे विस्तार के प्रवृत्त होने पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तारीख से पर्याप्त विस्तार किया है।

सारणी

क्रम संख्या	प्रवर्ग	सीमेंट उद्योगों के सिवाय, औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए तारीख 01-08-2015 से प्रभार्य विद्युत शुल्क की विद्यमान दर	सीमेंट उद्योगों के सिवाय, औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए वर्ष 2016 के लिए विद्युत शुल्क की पुनरीक्षित दर
1	2	3	4
3.3	01-04-2014 के पश्चात् स्थापित मध्यम औद्योगिक इकाईयां।	पांच वर्ष के लिए पांच प्रतिशत	पांच वर्ष के लिए पांच प्रतिशत और पांच वर्ष पूर्ण हो जाने के पश्चात् स्तम्भ संख्या 4 के अधीन क्रम संख्या 3.2 के सामने विनिर्दिष्ट दर प्रभारित की जाएगी।

4.3	01-04-2014 के पश्चात् स्थापित लघु उद्योग।	पांच वर्ष के लिए दो प्रतिशत	पांच वर्ष के लिए दो प्रतिशत और पांच वर्ष पूर्ण हो जाने के पश्चात् स्तम्भ संख्या 4 के अधीन क्रम संख्या 4.2 के सामने विनिर्दिष्ट दर प्रभारित की जाएगी।
4.4	01-08-2015 के पश्चात् स्थापित नए लघु उद्योग।	पांच वर्ष के लिए एक प्रतिशत	पांच वर्ष के लिए एक प्रतिशत और पांच वर्ष पूर्ण हो जाने के पश्चात् स्तम्भ संख्या 4 के अधीन क्रम संख्या 4.2 के सामने विनिर्दिष्ट दर प्रभारित की जाएगी।
5.	ई.एच.टी. प्रवर्ग सहित नया उद्योग जो तीन सौ से अधिक हिमाचल के निवासी नियोजित करता है।	पांच वर्ष के लिए एक प्रतिशत	पांच वर्ष के लिए एक प्रतिशत और पांच वर्ष पूर्ण हो जाने के पश्चात् अपने-अपने प्रवर्ग की औद्योगिक इकाई के अधीन दी गई ई0 डी0 (विद्युत शुल्क) दर प्रभारित की जाएगी।
6.	विद्यमान औद्योगिक इकाईयां जिन्होंने 31-03-2016 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है और जिन्होंने 31-03-2016 के पश्चात्, हिमाचल प्रदेश में समय-समय पर यथा संशोधित औद्योगिक इकाईयों को अनुदान रियायतें और प्रसुविधाओं से सम्बन्धित नियम, 2004 के अधीन यथा परिभाषित, पर्याप्त विस्तार किया है।		विस्तारित क्षमता के प्रारम्भ की तारीख से पांच वर्ष के लिए एक प्रतिशत और पांच वर्ष पूर्ण हो जाने के पश्चात् अपने-अपने प्रवर्ग की औद्योगिक इकाई के अधीन दी गई ई0 डी0 (विद्युत शुल्क) दर प्रभारित की जाएगी।

आदेश द्वारा,
तरुण श्रीधर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (विद्युत)।

[Authoritative English text of this Department's Notification No. MPP-F(10)- 17/2012-I dated 27th February, 2017 as required under Clause (3) of article 348 of the Constitution of India.]

MPP & POWER DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 27th February, 2017

No. MPP-F (10)-17/2012-I.—In continuation and partial modification of this department's notifications bearing No. MPP-F(10)-17/2012, dated 10.09.2014 and 29.08.2015, the Governor,

Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 11 of the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Act, 2009 is pleased to impose Electricity Duty in respect of,—

- (a) New Industrial Units commencing commercial production on and after 01.08.2015; and
- (b) Existing industrial units, which have commenced commercial production upto 31.03.2016 and which undergo substantial expansion, as defined under “Rules Regarding Grant of Incentives, Concessions and Facilities to the Industrial Units in Himachal Pradesh, 2004” as amended from time to time, from the date of commencing commercial production of such expansion coming into effect;

In the public interest, as per table and manner given below:—

Table

Sr.No.	Category	Existing rate of Electricity Duty Chargeable w.e.f 01.08.2015 for Industrial consumers except Cement Industries.	Revised rate of Electricity Duty for the year 2016 for the Industrial consumers except Cement Industries.
1	2	3	4
3.3	Medium Industrial Units set up after 01.04.2014	5% for 5 years	5% for 5 years and after completion of 5 years rate under column No. 4 specified against Sr. No. 3.2 shall be charged
4.3	Small Industry set up after 01.04.2014	2% for 5 years	2% for 5 years and after completion of 5 years rate under column No. 4 specified against Sr. No. 4.2 shall be charged
4.4	Small Industry set up after 01.08.2015	1% for 5 years	1% for 5 years and after completion of 5 years rate under column No. 4 specified against Sr. No. 4.2 shall be charged.
5	New Industry including EHT category which employ more than 300 Himachalis	1% for 5 years	1% for 5 years and after completion of 5 years ED rate given under respective category of industry shall be charged.

6	Existing Industrial unit which has commenced commercial production up to 31.03.2016 and which undergoes substantial expansion after 31.03.2016, as defined under “Rules Regarding Grant of Incentives, Concessions and Facilities to Industrial Units in HP, 2004” and as amended from time to time.		1% for 5 years from the date of commencement of expanded capacity and after completion of 5 years ED rate given under respective category of industry shall be charged.
---	--	--	---

By order,
TARUN SHRIDHAR,
Addl. Chief Secretary (Power).

**In the Court of Shri Balwan Chand, HAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Sujanpur, District Hamirpur, H. P.-176 110**

In the matter of :

1. Sushil Kumar aged 27 years s/o Shri Om Prakash, r/o Village Bhiar, P.O. Mehal, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, H.P. at present c/o Onkar s/o Jyoti, r/o ward No. 6, Acharya Mohalla, Post Office & Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (HP).
2. Sheetal Kumari aged 26 years d/o Shri Chaman Lal, r/o Village Charjehri, P.O. Mehal, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, H.P.

Versus

General Public

Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Sushil Kumar aged 27 years s/o Shri Om Prakash, r/o Village Bhiar, P.O. Mehal, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, H.P. at present c/o Onkar s/o Jyoti, r/o ward No. 6 Acharya Mohalla, Post Office & Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (HP) and Sheetal Kumari aged 26 years d/o Shri Chaman Lal, r/o Village Charjehri, P.O. Mehal, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, H.P. have filed an application alongwith affidavits in this court under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 15-01-2017 at Nawahi Devi Mata Mandir, Tehsil Sarkaghat, District Hamirpur HP as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objections regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 10-03-2017. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 04-02-2017 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).*

**In the Court of Shri Balwan Chand, HAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Sujanpur, District Hamirpur, H. P.-176 110**

In the matter of :

1. Shri Sukh Devi Singh aged 40 years s/o Shri Baljit Singh, r/o Village Bugdhar, P.O. Chabutra, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).
2. Ratto Francine aged 60 years d/o Shri Ratto Yves, r/o 3 Rue Des Frenes 25370 Rochejean (France). . . *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.—Notice of the Intended Marriage.

Shri Sukh Devi Singh aged 40 years s/o Shri Baljit Singh, r/o Village Bugdhar, P.O. Chabutra, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) and Ratto Francine aged 60 years d/o Shri Ratto Yves, r/o 3 Rue Des Frenes 25370 Rochejean (France) have filed an application in the court of undersigned under section 5 of Special Marriage Act, 1954 in which they stated that they intend to solemnize their marriage within three months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objections regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 29-04-2017. The objections received after 29-04-2017 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 28-01-2017 under my hand and seal of the court.

Seal.

BALWAN CHAND (HAS),
*Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).*

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा**मुकद्दमा नं० :**

Migmar

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Migmar Wangmod पुत्री Late श्री Cheme Dorjee, निवासी Mcleodganj, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री Tenzin Choezon की जन्म तिथि 29-11-2009 है परन्तु M.C. Dharamshala में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Tenzin Choezon की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 3-3-2017 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 9-2-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर अदालत।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा**मुकद्दमा नं० :**

Mohinder Kaur

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Mohinder Kaur पत्नी श्री Surinder Kaur, निवासी K.B. D/Shala, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री Manjeet Kaur की जन्म तिथि 01-09-1995 है परन्तु M. C. Dharamshala में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Manjeet Kaur की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 3-3-2017 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 9-2-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर अदालत।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा

मुकद्दमा नं० :

श्री मान सिंह

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री मान सिंह पुत्र श्री Brij Lal, निवासी Tikabani Yol, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पत्नी Smt. Chanda की मृत्यु तिथि 25-06-2000 है परन्तु M. C. Dharamshala में मृत्यु तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Smt. Chanda की मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 3-3-2017 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 14-2-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर अदालत।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

**In the Court of Shri Gian Sagar Negi, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),
District Shimla (H. P.)**

Shri Madan Lal Sharma s/o Lt. Shri Ghana Nand Sharma, r/o Village Nagri, P.O. Salana, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Shri Madan Lal Sharma s/o Lt. Shri Ghana Nand Sharma, r/o Village Nagri, P.O. Salana, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application along with affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Births & Deaths Registration Act, 1969 to enter the date of birth of her daughter named—Ms Manisha Sharma d/o Shri Madan Lal Sharma s/o Lt. Shri Ghana Nand Sharma, r/o Village Nagri, P.O. Salana, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Thari, Shimla.

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of Birth
1.	Ms. Manisha Sharma	Daughter	06-01-1983

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding date of birth of above named in the record of Gram Panchayat Thari, Shimla may file

their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 27-02-2017 under my signature and seal of the court.

Seal.

GIAN SAGAR NEGI,
*Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla.*

**In the Court of Shri H. S. Rana, H.A.S., Marriage Officer (SDM) Paonta Sahib,
District Sirmaur, Himachal Pradesh**

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

In the matter of :

Shri Sukhil Reen s/o Shri Narinder Reen, r/o Flat No. 414 Tri City Homes, Peer Muchalla, Punjab at present Shah Niwas, Ward No. 8, Paonta Sahib, District Sirmaur, HP and Ma Christine Atanacio Arches d/o Mr. Elmer Arches, r/o Block 6, Lot 59, Phase 3D Dagatdagatan, Caloocan City Philippines.

Versus

General Public

An Application for registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.

Shri Sukhil Reen s/o Shri Narinder Reen, r/o Flat No. 414 Tri City Homes, Peer Muchalla, Punjab at present Shah Niwas, Ward No. 8, Paonta Sahib, District Sirmaur, HP and Ma Christine Atanacio Arches d/o Mr. Elmer Arches, r/o Block 6, Lot 59, Phase 3D Dagatdagatan, Caloocan City Philippines has presented before the undersigned on dated 31-01-2017 for registration of their marriage solemnized between them on 30-01-2017 and have been living as husband and wife ever since then. Notices are given to all concerned and General Public to this effect that if any body have any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 30-01-2017 of Shri Sukhil Reen s/o Shri Narinder Reen, r/o Flat No. 414 Tri City Homes, Peer Muchalla, Punjab at present Shah Niwas, Ward No. 8, Paonta Sahib, District Sirmaur, HP and Ma Christine Atanacio Arches d/o Mr. Elmer Arches, r/o Block 6, Lot 59, Phase 3D Dagatdagatan, Caloocan City Philippines he should file written objections and appear personally or through an authorized agent before this court within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court.

Issued under my hand and office seal of this court on 31-01-2017.

Seal.

HARI SINGH RANA (HAS),
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.*

ब अदालत श्री हरि सिंह राणा, हि0प्र0से0, अतिरिक्त जिला पंजीयक विवाह एवं उप-मण्डल अधिकारी (ना0) पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्री राजेश कुमार पुत्र आज्ञा राम, निवासी ग्राम बांयकुआं, डा0 पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. सचिव ग्राम पंचायत जामनीवाला, पांवटा साहिब
2. आम जनता।

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 8(4) के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण बारे।

जैसा कि श्री राजेश कुमार पुत्र आज्ञा राम, निवासी ग्राम बांयकुआं, डा0 पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह श्रीमती वर्षा देवी पुत्री श्री रमेश चन्द, निवासी ग्राम मलघोटा, डा0 खडानाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के साथ दिनांक 22-12-2014 को हुआ है तथा अज्ञानतावश ग्राम पंचायत जामनीवाला, तहसील पांवटा साहिब के रिकार्ड में विवाह का पंजीकरण नहीं करवा सका है जिसे अब पंजीकरण करवाना चाहता है।

अतः इस सम्बन्ध में जैसा कि श्री राजेश कुमार पुत्र आज्ञा राम, निवासी ग्राम बांयकुआं, डा0 पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के विवाह के पंजीकरण बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो दिनांक 03-03-2017 तक असालतन अथवा वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तिथि तक कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थी का विवाह पंजीकरण एवं दर्ज करने के नियमानुसार आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 01-02-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हरि सिंह राणा (हि0प्र0से0),
अतिरिक्त जिला पंजीयक विवाह एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी (ना0),
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री हरि सिंह राणा, हि0प्र0से0, अतिरिक्त जिला पंजीयक विवाह एवं उप-मण्डल अधिकारी (ना0) पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्री सुरजीत सिंह पुत्र अन्नत राम, निवासी देवी नगर पांवटा, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका पांवटा साहिब
2. आम जनता।

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 8(4) के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण बारे।

जैसा कि श्री सुरजीत सिंह पुत्र अन्नत राम, निवासी देवी नगर पांवटा, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह श्रीमती बबीता पुत्री श्री राजकुमार, निवासी

ग्राम सलेमपुर गाडा, जिला सहारनपुर के साथ दिनांक 13-07-2016 को हुआ है तथा अज्ञानतावश ग्राम पंचायत जामनीवाला, तहसील पांवटा साहिब के रिकार्ड में विवाह का पंजीकरण नहीं करवा सका है जिसे अब पंजीकरण करवाना चाहता है।

अतः इस सम्बन्ध में जैसा कि श्री सुरजीत सिंह पुत्र अन्नत राम, निवासी देवी नगर पांवटा, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के विवाह के पंजीकरण बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो दिनांक 03-03-2017 तक असालतन अथवा वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तिथि तक कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थी का विवाह पंजीकरण एवं दर्ज करने के नियमानुसार आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 01-02-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हरि सिंह राणा (हि0प्र0से0),
अतिरिक्त जिला पंजीयक विवाह एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी (ना0),
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

**In the Court of Shri H. S. Rana, H.A.S., Marriage Officer (SDM) Paonta Sahib,
District Sirmaur, Himachal Pradesh**

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

In the matter of :

Shri Kapil Singal s/o Shri Ram Kumar Singal, r/o Ogli, Singla Niwas Kala Amb, District Sirmaur, at present Ward No. 6, Shamsherpur, Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Renu Chauhan d/o Shri Paramjit Singh, r/o Village Mashu, Sub-Tehsil Kamrau, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.

Versus

General Public

An Application for registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.

Shri Kapil Singal s/o Shri Ram Kumar Singal, r/o Ogli, Singla Niwas Kala Amb, District Sirmaur, at present Ward No. 6, Shamsherpur, Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Renu Chauhan d/o Shri Paramjit Singh, r/o Village Mashu, Sub-Tehsil Kamrau, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. has presented before the undersigned on dated 31-01-2017 for registration of their marriage solemnized between them on 14-07-2016 and they have been living as husband and wife ever since then. Notices are given to all concerned and General Public to this effect that if any body have any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 14-07-2016 of Shri Kapil Singal s/o Shri Ram Kumar Singal, r/o Ogli, Singla Niwas Kala Amb, District Sirmaur, at present Ward No. 6, Shamsherpur, Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Renu Chauhan d/o Shri Paramjit Singh, r/o Village Mashu, Sub-Tehsil Kamrau, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. he should file written objections and appear personally or through an authorized agent before

this court within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court.

Issued under my hand and office seal of this court on 31-01-2017.

Seal.

HARI SINGH RANA (HAS),
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.

CHANGE OF NAME

I, Arpna Thakur w/o Shri S. N. Thakur, r/o Dhaulakuan, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my name from Arpna Mehra to Arpna Thakur. All concerned please note that.

ARPNA THAKUR,
w/o Shri S. N. Thakur,
r/o Dhaulakuan, Tehsil Paonta Sahib,
District Sirmaur (H.P.).